प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

रिट याचिका क्रमांक 1427/2004

याचिकाकर्ता: दुखूराम

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

उपस्थित:-

• याचिकाकर्ता की ओर से श्री सूर्यकांत मिश्रा, अधिवक्ता।

• राज्य/उत्तरवादीगण क्रमांक 1 और 2 की ओर से श्री वी.वी.एस. मूर्ति, उप महाधिवक्ता।

• उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के लिए कोई नहीं।

<u>मौखिक आदेश</u>

(30**मार्च, 2011 को पारित)**

यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अपने बेटे की उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 की हिरासत में हुई मृत्यु के कारण ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) के मुआवजे की मांग के लिए दायर की गई है।

2. मृतक खीखराम याचिकाकर्ता का बेटा था। चोरी के आरोप में, मृतक खीखराम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मृतक खीखराम द्वारा एक गुप्त स्थान पर छिपाए गए कथित सामान की बरामदगी के लिए, उसे उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 द्वारा एक होमगार्ड के साथ ग्राम-रायपुर के कुम्हिया तालाब (पुलिस थाना- बरद्वार) लाया गया। जाँच के दौरान, पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के मृतक बेटे से पीतल के बर्तन छिपाने की जगह के बारे में पूछताछ की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता का मामला है कि जब उसके बेटे ने यह खुलासा किया कि बर्तन तालाब के अंदर रखा गया था, तो उसके बेटे को तालाब में गोता लगाने और बर्तन निकालने के लिए मजबूर किया गया। उस समय मृतक खीखराम हथकड़ी और जंजीर से बंधा हुआ था। इस तरह जोर दिए जाने पर, खीखराम तालाब में उतरा, लेकिन कभी बाहर नहीं आया। पुलिस अधिकारियों ने मृतक को खोजने की कोशिश की खीखराम को तालाब में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद वे वहाँ

इकट्ठे हुए ग्रामीणों को यह कहते हुए कि मृतक खीखराम को ढूंढे, वहाँ से चले गये। इसके बाद, दिनांक 21/10/97 को मृतक खीखराम का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया। मर्ग (मृत्यु की सूचना) दर्ज की गई और एक पंचनामा (अनुलग्नक पी12) भी तैयार किया गया। मृतक खीखराम के शव को शवपरीक्षण के लिए भेजा गया और शवपरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि मृत्यु का कारण श्वासावरोध है और यह शरीर के लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण हो सकता है। मामले की जाँच की गई और उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के खिलाफ धारा 304-ए/34 भा.द.वि. के तहत कथित अपराध के आरोप में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती की अदालत में अभियोग पत्र दायर की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 - पुलिस अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण हुई, जब वह उनकी हिरासत में था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि जिस तरह से उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 ने उनके बेटे के साथ व्यवहार किया, उसके परिणामस्वरूप उनके बेटे की अकाल मृत्यु हो गई। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह उत्तरवादी 3 और 4 ही थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता के बेटे को, भले ही उस पर चोरी का आरोप था, पानी में डूबने के लिए मजबूर किया, जबकि उनका बेटा हथकड़ी और जंजीर से बंधा हुआ था। उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 की इस मनमानी

कार्रवाई के कारण, याचिकाकर्ता के बेटे ने अपना जीवन खो दिया, जिसके लिए याचिकाकर्ता मुआवजा पाने का हकदार है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु उत्तरवादी 3 और 4 की हिरासत में, उनकी शुद्ध लापरवाही, कठोर और गैर-जिम्मेदार कृत्य के कारण हुई।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना होने के बाद, जिसमें याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु हुई, मामले की जाँच की गई और उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के खिलाफ धारा 304-ए/34 भा.द.वि. के तहत अपराध किए जाने के आरोप में एक दांडिक मामला दर्ज किया गया। एक अभियोग पत्र दायर की गई और उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 पर मुकदमा चलाया गया। दांडिक प्रकरण क्रमांक 4031/02 में पारित दिनांक 18/2/08 के फैसले के अनुसार, उत्तरवादी क्रमांक 3 को दोषी पाया गया और उसे दोषसिद्ध ठहराया गया, जबकि विद्वान विचारण न्यायलय ने उत्तरवादी क्रमांक 4 को दोषमुक्त कर दिया है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत करते हैं कि गलत काम करने वाले को कानून के अनुसार दंडित किया गया है और यदि याचिकाकर्ता अपने बेटे की मृत्यु के कारण मुआवजे का दावा करता है, तो उसे इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने के बजाय व्यव्हार न्यायलय में मुकदमा दायर करना चाहिए था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया हैं कि मुआवजे के अनुदान से संबंधित मामले में सबूत दर्ज करने और तथ्यों के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विवादित प्रश्नों की जाँच की आवश्यकता होगी। इसलिए, रिट याचिका उपयुक्त उपाय नहीं है और खारिज किए जाने योग्य है।

5. उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 की ओर से दिए गए जवाब में, यह कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 केवल पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, जाँच के दौरान, छिपाई/चोरी की गई वस्तु की बरामदगी के उद्देश्य से। याचिकाकर्ता के बेटे से उस जगह से छिपे हुए बर्तन को निकालने के लिए कहा गया, जहाँ उसने चोरी किया हुआ बर्तन रखने की बात कही थी। मृतक खीखराम को बर्तन निकालने के लिए पानी में उतरने के लिए कहने से पहले, यह सत्यापित किया गया था कि वह तैरना जानता है और तभी उसे पानी में उतरने और तालाब से चोरी की गई वस्तु को निकालने के लिए कहा गया। मृतक को एक हाथ में हथकड़ी लगाई गई थी क्योंकि वह आदतन अपराधी था और उसके खिलाफ कई दांडिक मामले दर्ज थे। जब मृतक तालाब से बाहर नहीं आया, तो मृतक को खोजने के लिए सभी प्रयास किए गए और मृतक को बाहर निकालने के लिए पानी में मछली पकड़ने का जाल भी फेंका गया। इसलिए, उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 मृतक खीखराम की आकस्मिक मृत्यु के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं और उन्होंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। इस बात पर विवाद नहीं है कि दिनांक 19/10/97 को मृतक खीखराम को हिरासत में तालाब के पास लाया गया था

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी क्रमांक 3 और उत्तरवादी क्रमांक 4 भी उसके साथ थे, और मृतक खीखराम का बर्तन निकालने के लिए पानी में उतरना उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 द्वारा विवादित नहीं है। यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा मृतक को बर्तन निकालने के लिए पानी में उतरने के लिए कहा गया था। मृतक का शव उसी तालाब से दिनांक 21/10/97 को बरामद किया गया था।

6. दिनांक 18/2/08 के फैसले में, विचारण न्यायलय ने उत्तरवादी क्रमांक 3 को धारा 304-ए/34 भा.द.वि. के तहत अपराध करने का दोषी पाया है, हालाँकि उत्तरवादी क्रमांक 4 को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है। विचारण न्यायलय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि उत्तरवादी 3 और 4 मृतक खीखराम को तालाब पर ले गए थे और उसे हथकड़ी और जंजीर से बंधे होने के बावजूद बर्तन निकालने के लिए अंदर जाने का निर्देश दिया गया था और उसके बाद, मृतक बाहर नहीं आ सका और दो दिन बाद, उसका शव उसी तालाब से बरामद किया गया। विचारण न्यायलय का फैसला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मृतक खीखराम की मृत्यु उत्तरवादी क्रमांक 3 के लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इसलिए, विचार के लिए उठने वाला प्रश्न यह है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका में, याचिकाकर्ता को मुआवजा दिया जा सकता है। यह मुद्दा अब कोई अनिर्णीत मुद्दा नहीं रह गया है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

निर्णयों की एक श्रृंखला में स्थापित किया जा चुका है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करने के लिए राज्य का मुआवजा देने का दायित्व, संविधान द्वारा बनाया गया सार्वजनिक कानून में एक नया दायित्व है, और यह प्रतिनिधिक या अपकृत्य का दायित्व नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा जीवन से वंचित होने के लिए मुआवजे का सार्वजनिक कानून में एक दावा है। **रुदुल साह बनाम बिहार राज्य और अन्य AIR 1983 SC 1086** के मामले में, वैकल्पिक उपाय के अस्तित्व पर राज्य की आपत्ति को खारिज करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. यह सच है कि अनुच्छेद 32 का उपयोग उन अधिकारों और दायित्वों को लागू करने के लिए एक स्थानापन्न के रूप में नहीं किया जा सकता है जिन्हें सिविल और दांडिक अदालतों की सामान्य प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इसलिए एक धन के दावे को सबसे अधीनस्त सक्षम अदालत में दायर एक मुकदमे में उठाया जाना चाहिए और उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे विचार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय धन के भुगतान का आदेश पारित कर सकता है, यदि ऐसा आदेश मौलिक अधिकार से वंचित किए जाने के परिणामस्वरूप

मुआवजे की प्रकृति का है। वर्तमान मामला ऐसे मामलों का एक उदाहरण है। याचिकाकर्ता को एक पूर्ण मुकदमे में दोषमुक्त होने के बाद भी 14 साल से अधिक समय तक अवैध रूप से जेल में हिरासत में रखा गया था। उसने अवैध हिरासत से रिहाई के लिए इस न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उसने वह अनुतोष प्राप्त की, हमारा निष्कर्ष यह था कि दोषमुक्त होने के बाद जेल में उसकी हिरासत पूरी तरह से अन्यायपूर्ण थी। उसका तर्क है कि वह अपनी अवैध हिरासत के लिए मुआवजा पाने का हकदार है और हमें इस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में ही मुआवजे के भुगतान के लिए एक उपयुक्त आदेश पारित करना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. हम इस तर्क का विरोध नहीं कर सकते। हमें इसका कोई प्रभावी उत्तर नहीं दिखता, सिवाय इस घिसे-पिटे और व्यर्थ आपत्ति के कि यदि याचिकाकर्ता चाहे, तो राज्य सरकार से हर्जाना वसूलने के लिए एक मुकदमा दायर कर सकता है। संयोग से राज्य के अधिवक्ता ने यह आपत्ति नहीं उठाई है। याचिकाकर्ता को एक सामान्य मुकदमे के लिए तब भेजा जा सकता था जब मुआवजे का उसका दावा तथ्यात्मक रूप से विवादास्पद होता, इस अर्थ में कि एक व्यवहार न्यायलय उसके दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी। लेकिन हमें कोई संदेह नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी अवैध

हिरासत के लिए हर्जाना वसूलने के लिए एक मुकदमा दायर करता है, तो उस मुकदमे में हर्जाने की डिक्री पारित करनी होगी, हालांकि सबूतों के अभाव में, यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि उसके पक्ष में सटीक राशि क्या होगी। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में मुआवजे का आदेश पारित करने से इनकार करना, स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकार के लिए केवल कोरा समर्थन होगा जिसे राज्य सरकार ने इतनी घोर रूप से उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, अपनी महत्वपूर्ण सामग्री से वंचित हो जाएगा यदि इस न्यायालय की शक्ति अवैध हिरासत से रिहाई के आदेश पारित करने तक ही सीमित हो। उस अधिकार के उल्लंघन को उचित रूप से रोकने और अनुच्छेद 21 के अधिदेश के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने के तरीकों में से एक यह है कि इसके उल्लंघनकर्ताओं को मौद्रिक मुआवजा देने के लिए दंडित किया जाए। प्रशासनिक (कठोरता) जिसके कारण मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन होता है, उसे न्यायपालिका द्वारा अपनाए जाने वाले किसी अन्य तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। मुआवजे का अधिकार उन उपकरणों के गैरकानूनी कृत्यों के लिए कुछ उपशामक है जो सार्वजनिक हित के नाम पर कार्य करते हैं और जो राज्य की शक्तियों को एक ढाल के रूप में अपनी सुरक्षा के लिए प्रस्तुत करते हैं। यदि इस देश में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2011:CGHC:9249

सभ्यता को नष्ट नहीं होना है, जैसा कि कुछ अन्य देशों में हुआ है जिनका उल्लेख करना दुखद है, तो हमें खुद को यह स्वीकार करने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है कि व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति सम्मान ही लोकतंत्र का सच्चा आधार है। इसलिए, राज्य को याचिकाकर्ता के अधिकारों को उसके अधिकारियों द्वारा किए गए नुकसान की मरम्मत करनी चाहिए। वह उन अधिकारियों के खिलाफ मुआवजा वसूलने का सहारा ले सकता है।"

8. **नीलाबाती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य AIR 1993 SC 1960** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उड़ीसा राज्य को मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुआवजा देते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9.... इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में मुआवजे का अवार्ड, सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कठोर दायित्व पर आधारित है, जिस पर संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, भले ही यह अपकृत्य पर आधारित कार्रवाई में निजी कानून में एक बचाव के रूप में उपलब्ध हो सकता है। यह दोनों उपायों के बीच एक अंतर है।" वर्मा, जे. ने आगे समझाया कि राज्य का अपने कर्मचारियों के अपकृत्यपूर्ण कृत्यों के लिए संप्रभु उन्मुक्ति का दावा

2011:CGHC:9249

केवल दायित्व के क्षेत्र तक ही सीमित है अपकृत्य में सीमित है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य के दायित्व से अलग है जिस पर संवैधानिक योजना में संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता है, और यह संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत संवैधानिक उपाय के लिए कोई बचाव नहीं है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजे दिए जाने हेतु सक्षम बनाता है, जब मौलिक अधिकारों को लागू करने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका मुआवजे प्रदान करना हो सकता है। वर्मा, जे. से सहमत होते हुए, डॉ. ए.एस. आनंद, जे. ने उसी मामले में अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"सार्वजनिक कानून का उद्देश्य न केवल सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाना है, बल्कि नागरिकों को यह आश्वासन देना भी है कि वे एक ऐसी कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जिसका उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को संरक्षित करना है - नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता के रक्षक होने के नाते, इस न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास न केवल शक्ति और क्षेत्राधिकार है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, पीड़ित या पीड़ित के वारिस को अनुतोष प्रदान करने का दायित्व भी है, जिनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ है, और राज्य को यह निर्देश देकर कि वह अपने अधिकारियों द्वारा नागरिकों के

2011:CGHC:9249

मौलिक अधिकारों को पहुँचाए गए नुकसान की मरम्मत करे, भले ही नागरिक के पास मुकदमे या दांडिक कार्यवाही के माध्यम से उपचार का अधिकार हो। राज्य के पास निश्चित रूप से गलत काम करने वाले के खिलाफ कानून के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही के माध्यम से क्षतिपूर्ति पाने और कार्रवाई करने का अधिकार है।" डॉ. आनंद, जे. ने यह भी अवलोकन किया: "पुलिस या जेल अधिकारियों पर यह एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी हिरासत में मौजूद नागरिक को उसके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय में **डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1997 SC 610** के मामले में फिर से विचार किया गया, जिसमें पहले के फैसलों की समीक्षा के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि सार्वजनिक कानून के तहत "कठोर दायित्व के सिद्धांतों" पर आधारित राज्य के विरुद्ध मुआवजे का अनुतोष ऐसी है जिस पर संप्रभु उन्मुक्ति का बचाव लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है और यह अनुतोष पारंपरिक उपचारों के अतिरिक्त है और किसी दिए गए मामले में प्रदान किए गए मुआवजे को सिविल वाद में हर्जाने के रूप में दावेदार को प्रदान की गई किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है। यह भी माना गया कि अनुच्छेद 32 या 226 के तहत मुआवजे के मूल्यांकन में, "जोर

क्षतिपूरक तत्व पर होना चाहिए न कि दंडात्मक तत्व पर।" यह आगे माना गया कि उद्देश्य घावों पर मरहम लगाना है न कि उल्लंघनकर्ता या अपराधी को दंडित करना, क्योंकि अपराध के लिए उपयुक्त दंड देना (मुआवजे की परवाह किए बिना) उस दांडिक न्यायालय पर छोड़ देना चाहिए जिसमें अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, जिसे करने के लिए राज्य कानूनन कर्तव्यबद्ध है।

10. **<u>हिंदुस्तान पेपर्स कॉर्पोरेशन बनाम अनंत भट्टाचार्जी 2004 (6) SCC 213</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"मुआवजे के अनुदान के उद्देश्य से सार्वजनिक कानून के उपाय का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब किसी नागरिक के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है न कि अन्यथा।" न्यायालय ने आगे कहा कि "संविधान या किसी क़ानून के हर प्रावधान का उल्लंघन न्यायालय को मुआवजे के अनुदान का निर्देश देने में सक्षम नहीं बनाएगा।"

11. इसलिए, यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करके मुआवजे का दावा करना सार्वजनिक कानून में मांगा गया एक उपाय है और यह न्यायालय, उचित मुआवजे का दावा करने के सामान्य सिविल

उपाय के अस्तित्व के बावजूद, ऊपर संदर्भित निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करते हुए, मुआवजा प्रदान कर सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **पूरन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य AIR 2003 मध्य प्रदेश 53** के मामले में भी यही विचार अपनाया है।

12. रुदुल साह (पूर्वोक्त) के मामले में, यह पाया गया था कि याचिकाकर्ता को अवैध हिरासत का सामना करना पड़ा था। याचिकाकर्ता पर हुए गंभीर अन्याय को ठीक करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम उपाय के रूप में मुआवजे प्रदान किया और यह अवलोकन किया कि एकमुश्त मुआवजे प्रदान किया जाना याचिकाकर्ता को राज्य और उसके गलती करने वाले अधिकारियों से आगे के हर्जाने की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने से नहीं रोकेगा, यह देखते हुए कि मुआवजे का आदेश एक उपशामक की प्रकृति का है। नीलाबाती बेहरा (पूर्वोक्त) के मामले में, हिरासत में मौत के एक मामले में ₹1,50,000/- का मुआवजा दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. मृतक एक युवक था जिसकी मृत्यु उन परिस्थितियों में हुई जब वह उत्तरवादी 3 और 4 के नियंत्रण और हिरासत में था। मामले की समग्र परिस्थितियों और ऊपर संदर्भित विभिन्न फैसलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की राय में, राज्य द्वारा याचिकाकर्ता को ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) की मुआवजे की राशि का भुगतान

2011:CGHC:9249

किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता इस तरह दिए गए राशि से असंतुष्ट है, तो वह पारंपरिक उपचारों का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा और वर्तमान मामले में दिए गए मुआवजे को उसके द्वारा दायर किए गए (यदि कोई हो) व्यव्हार (सिविल) वाद मुकदमे में हर्जाने के रूप में उसे दी गई किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

14. तदनुसार, याचिका को ऊपर बताए गए सीमा तक स्वीकार किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दीप्ति

हस्ता.

मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायाधीश

2011:CGHC:9249

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Ajey kumar

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur